भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2295
उत्तर देने की तारीख-09/12/2024

ग्रामीण साक्षरता दर

†2295. **श्रीमती शांभवी:**
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री नरेश गणपत म्हस्के:
श्री राजेश वर्मा:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दशक में ग्रामीण साक्षरता दर में वृद्धि के संबंध में आंकड़े क्या हैं;
(ख) क्या सरकार की पहलों का इस वृद्धि में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक विश्लेषण क्या है;
(ग) विगत दस वर्षों के दौरान ग्रामीण साक्षरता में स्त्री-पुरुष अंतर संबंधी आंकड़े क्या हैं; और
(घ) शत-प्रतिशत ग्रामीण साक्षरता प्राप्त करने में सरकार को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार द्वारा विशेषकर महाराष्ट्र और बिहार में उनके समाधान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (घ): विगत दशक से ग्रामीण साक्षरता दर में वृद्धि निम्नानुसार है:

(प्रतिशत में)

ग्रामीण साक्षरता दर (7 वर्ष और उससे अधिक)	2011 (वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार)	2023-24 (वर्ष 2023-24 के पीएलएफएस के अनुसार)
	67.77	77.5

पिछले दस वर्षों के दौरान ग्रामीण साक्षरता दर में जेंडर अंतराल निम्नानुसार है:

(प्रतिशत में)

जेंडर के आधार पर ग्रामीण साक्षरता दर (7 वर्ष और उससे अधिक)	2011 (वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार)		2023-24 (वर्ष 2023-24 के पीएलएफएस के अनुसार)	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
	77.15	57.93	84.7	70.4

भारत सरकार ने देश में वयस्कों के बीच ग्रामीण साक्षरता दर सहित साक्षरता दर में सुधार करने हेतु, समय-समय पर अनेक केंद्र प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम जैसे समग्र शिक्षा अभियान (वर्ष 2018-19 से वर्ष 2025-26), साक्षर भारत (वर्ष 2009-10 से वर्ष 2017-18), पढ़ना लिखना अभियान (वर्ष 2020-21 से वर्ष 2021-22) और उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/एनआईएलपी (वर्ष 2022-23 से वर्ष 2026-27) शुरू किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आए हैं।

भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से 2027 तक नव भारत साक्षरता कार्यक्रम (एनआईएलपी) नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया है, जिसे उल्लास: समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ के रूप में जाना जाता है। एनईपी 2020 के अनुरूप यह योजना उन वयस्कों (15 वर्ष और उससे अधिक आयु) को लक्षित करती है जो स्कूल नहीं जा सके और यह ग्रामीण क्षेत्रों, शैक्षिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों, महिलाओं आदि पर केंद्रित है। यह योजना हाइब्रिड मोड में कार्यान्वित की गई है, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास ऑफलाइन, ऑनलाइन या संयुक्त दृष्टिकोण अपनाने की छूट है। इस योजना के पाँच घटक हैं: (i) बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान, (ii) महत्वपूर्ण जीवन कौशल, (iii) बुनियादी शिक्षा, (iv) व्यावसायिक कौशल और (v) सतत शिक्षा। शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों को पंजीकृत करने हेतु एक समर्पित उल्लास मोबाइल ऐप विकसित किया गया है और यह 26 भाषाओं में प्राइमर तक पहुँच प्रदान करके शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को भी सक्षम बनाता है। निरंतर प्रयासों से, उल्लास के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक शिक्षार्थियों को पंजीकृत किया

गया है और 1 करोड़ से अधिक शिक्षार्थी पहले ही देश भर में बुनियादी साक्षरता और संख्याज्ञान मूल्यांकन परीक्षा (एफ़एलएनएटी) नामक साक्षरता परीक्षा में उपस्थित हो चुके हैं।

ग्रामीण साक्षरता में 100% का लक्ष्य प्राप्त करने में देश में प्रचलित कई भाषाओं के साथ बड़ी संख्या में आबादी, कई संस्कृतियों का संदर्भ और अव्यवस्थित अधिगम व्यवस्था जैसी कठिनाइयां हैं। उपर्युक्त बातों के मद्देनजर इस योजना को ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों पद्धतियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस योजना में शिक्षण और अधिगम का कार्य स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र भी इस योजना को कार्यान्वित कर रहा है और 10.87 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को उल्लास योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। राज्य ने अपना पहला एफ़एलएनएटी आयोजित किया है जिसमें 4 लाख से अधिक शिक्षार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए है। बिहार राज्य ने अभी तक उल्लास योजना को कार्यान्वित नहीं किया है।

*****